ऑटो-रिक्शा चालकों को घर खर्च के साथ किस्त की चिंता सता रही

हिन्दुस्तान घंटी बजाओ

दिल्ली में लॉकडाउन लगने के बाद तिपहिया वाहन चालकों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन बढ़ने और संक्रमण के डर से 50 फीसदी चालक गृह जनपद लौट गए हैं। वहीं, मौजूद चालकों में से किसी को घर के खर्च की चिंता है तो कोई किस्त भरने को परेशान है। हिन्दुस्तान संवाददाता ने शुक्रवार को चालकों का हाल जाना। पेश है एक रिपोर्ट...

50 फीसदी चालक अपने गृह जनपद लौट गए, 15 फीसदी ही सड़कों पर

85 फीसदी तिपहिया वाहनो के पहिए थमे, आय नहीं होने से परेशान हैं चालक

70 हजार से अधिक ऑटो चालकों की 5-5 हजार रुपये की मदद की थी दिल्ली सरकार ने गत वर्ष

दिल्ली में लॉकडाउन के चलते शुक्रवार को अजमेरी गेट पार्किंग में खड़े तिपहिया वाहन। • हिन्दुस्तान

जब आमदनी नहीं हो रही तो स्कूल फीस कहां से भरें

हालात

ऑटो चालक गौरव राघव ने लोन पर तिपहिया यह सोचकर लिया था कि परिवार का पालन-पोषाण कर सकेगा। लेकिन वर्ष 2020 में लॉकडाउन फिर अब वर्ष 2021 में महामारी के प्रकोप के चलते फिर लॉकडाउन ने उनकी चिंता बढ़ा दी है। सड़कों पर सवारियां नहीं होने से दैनिक आमदनी न के बराबर हैं। कोई आमदनी नहीं होने से बच्चों की स्कूल फीस और ऑटो की किस्त चुकाने की चिंता सताने लगी है।

गुजारा चला रहेः बुजुर्ग मां, पत्नी व दो बच्चों की जिम्मेदारी उठा रहे गौरव के मुताबिक, इस समय ऑटो की किस्त नहीं निकल पा रही है। बच्चों की फीस भरने में परेशानी हो रही है। रोजाना का खाना खर्चा अलग से है। अगर लगातार कुछ दिन और लॉकडाउन बढ़ गया तो आगे क्या होगा यही उन्हें चिंता है।

सवारी नहीं मिलने से घर का खर्च चलाना मुश्किल

फिक्र

ऑटो चालक सलीम का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से सवारी नहीं मिल रही है। दिनभर तिपहिया लेकर चौराहे पर खड़े होकर लौट आते हैं। रमजान के दिन चल रहे हैं। ऐसे में आमदनी नहीं होने से काफी परेशानी हो रही है। हम लोगों को घर खर्च चलाना भी मुश्किल हो रहा है। मैं भी घर से नहीं निकलना चाहता, लेकिन परिवार का पेट पालने के लिए निकलना पड़ता है। सरकार को हम लोगों की मदद के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए।

बीते वर्ष सरकार ने 5000 रुपये दिए थेः वर्ष 2020 में जब लॉकडाउन हुआ था तो दिल्ली सरकार ने 70 हजार से अधिक ऑटो चालकों को पांच हजार रुपये देकर आर्थिक मदद की थी। इस बार भी चालकों की मांग है कि आर्थिक मदद देकर सरकार उनकी मदद करे।

पार्किंग में खड़े किए

तिपहिया चालकों के मुताबिक, दिल्ली में कुल करीब 95 हजार तिपहिया वाहन चलते हैं। इनमें से तकरीबन 50 फीसदी तिपहिया चालक अपने गांव चले गए हैं। सड़क पर केवल 15 फीसदी तिपहिया वाहन चल रहे हैं। बाकी सब पार्किंग और घर में खड़े हैं। 85 फीसदी तिपहिया के पहिए थम गए हैं। स्टेशनों पर कई घंटे खड़े रहने पर बमुश्किल एक-दो सवारी मिलती है। सीएनजी तक का खर्च नहीं निकाल पा रहे हैं।

चालकों की रहने व खाने की व्यवस्था की जाए। पत्र लिखकर केंद्र और दिल्ली सरकार से मदद की गुहार लगाई है। रहने के लिए शिविर लगें। चालकों को घरों तक राशन किट पहुंचाई जाए। किस्त में ढिलाई देने के लिए लोन कंपनियों को निर्देश हों। **-राजेंद्र सोनी**, महामंत्री, दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ।

हेल्पलाइन नंबर

जिला	कंट्रोल रूम नंबर
पूर्वी	011-2051234
उत्तर पूर्व	011 22115289
शाहदरा	011 22111077
उत्तरी	011 27708768
मध्य	011 23270151
उत्तर पश्चिम	011 25951182
पश्चिम	011 25100096, 25195529
दक्षिण पश्चिम	011 25060031 25060032/50
नई दिल्ली	011 23385743
दक्षिण	011 29531277
दक्षिण पूर्व	011 26476415 26476416

आपदा प्रबंधन नंबर
1077

कोविड हेल्पलाइन नंबर
1075

हेल्पलाइन कोविड संक्रमित मरीज
1800111747

हेल्पलाइन नंबर
1031

कोविड कंट्रोल नंबर
011- 22391014, 2302441, 22304568, 22300012

'राशन की मांग पर सरकार जवाब दे'

नई दिल्ली (प्र.सं.)। उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना के तहत लॉकडाउन के दौरान गरीबों को राशन मुहैया कराने का आदेश देने की मांग पर दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। दिल्ली सरकार ने बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर 26 अप्रैल की सुबह तक लॉकडाउन लगाया है।

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने दिल्ली सरकार, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पीठ ने सभी पक्षकारों को अगली सुनवाई 13 मई से पहले जवाब देने को कहा है। पीठ ने यह आदेश एक गैर सरकारी संगठन की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है।

15 मई तक सिर्फ वर्चुअल सुनवाई

नई दिल्ली (प्र.सं.)। दिल्ली में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उच्च न्यायालय और जिला अदालतों में 15 मई तक सिर्फ वर्चुअल यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होगी। उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को यह आदेश जारी किया।

उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल मनोज जैन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि उच्च न्यायालय की सभी पीठ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सिर्फ 2021 में दाखिल अतिआवश्यक मामलों की ही सुनवाई करेंगी। आदेश में कहा गया है कि सभी रजिस्ट्रार और ज्वाइंट रजिस्ट्रार की अदालत भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सिर्फ जरूरी मामले सुनेंगी। साथ ही उच्च न्यायालय में 26 अप्रैल से 15 तक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध सभी मामलों को स्थगित कर दिया गया है। इन मामलों की सुनवाई नौ जुलाई से 31 जुलाई के बीच होगी।

अपनों ने शव लेने से इनकार किया

नई दिल्ली (व.सं.)। डर लोगों पर इस तरह हावी हो गया है कि अब कोरोना से मरने वाले लोगों का अंतिम संस्कार करने के लिए उनके घर वाले सामने नहीं आ रहे हैं। ऐसा ही मामला गोकलपुरी इलाके में सामने आया। जहां एक युवक की मौत के बाद उसके परिवार ने न तो शव ही लिया और न ही अंतिम संस्कार किया। ऐसे में दिल्ली पुलिस में तैनात एएसआई सुशील कुमार ने शव का अंतिम संस्कार किया।

पुलिस उपायुक्त संजय सेन ने बताया कि सोमवार दोपहर एक युवक की मौत की सूचना पर गोकलपुरी थाना पुलिस पहुंची। परिजनों ने बताया कि युवक सोनू कुमार की मौत बुखार से हुई है। पुलिस ने सोनू के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया। इस दौरान उसके परिजनों ने अस्पताल चलने और शव को हाथ लगाने से मना कर दिया।

HCL TECHNOLOGIES LIMITED

Corporate Identity Number : L74140DL1991PLC046369
Registered Office : 806, Siddharth, 96 Nehru Place, New Delhi, 110 019
Corporate Office : Plot No. 3A, Sector 126, Noida 201 304, U.P., India
Website: www.hcltech.com; Telephone: +91 11 26436336

Extract of Consolidated Financial Results of HCL Technologies Limited as per Ind AS: (₹ in crores)

Particulars	Three months ended (Audited)		Year ended (Audited)	
	31 March 2021	31 March 2020	31 March 2021	31 March 2020
Total income from operations	19,641	18,587	75,379	70,676
Net profit for the period before tax, exceptional and/or extraordinary items	3,367	3,885	15,853	13,980
Net profit for the period before tax	3,367	3,885	15,853	13,980
Net profit for the period after tax	1,111	3,172	11,169	11,057
Net profit for the period after tax and non-controlling interest	1,102	3,172	11,145	11,057
Total comprehensive income for the period (comprising profit for the period after tax and non-controlling interest and other comprehensive income after tax)	1,102	3,260	11,908	11,525
Equity share capital (par value ₹ 2 each)	543	543	543	543
Other equity	59,370	50,724	59,370	50,724
Earnings per equity share (of ₹ 2 /- each) (for continuing and discontinued operations) (₹)				
Basic (in ₹)	4.06	11.69	41.07	40.75
Diluted (in ₹)	4.06	11.69	41.07	40.75

Extract of Standalone Financial Results of HCL Technologies Limited as per Ind AS: (₹ in crores)

Particulars	Three months ended (Audited)		Year ended (Audited)	
	31 March 2021	31 March 2020 Refer note 4	31 March 2021	31 March 2020 Refer note 4
Total income from operations	9,249	9,067	35,673	32,666
Net profit for the period before tax, exceptional and/or extraordinary items	2,459	3,071	12,410	11,178
Net profit for the period before tax	2,459	3,071	12,410	11,178
Net profit for the period after tax	456	2,503	8,743	8,969
Total comprehensive income for the period (comprising profit for the period after tax and other comprehensive income after tax)	560	2,126	9,263	8,483
Equity share capital (par value ₹ 2 each)	543	543	543	543
Other equity	43,010	37,003	43,010	37,003
Earnings per equity share (of ₹ 2 /- each) (for continuing and discontinued operations) (₹)				
Basic (in ₹)	1.68	9.22	32.22	33.06
Diluted (in ₹)	1.68	9.22	32.22	33.05

Notes :

1. The consolidated and the standalone financial results for the three months and year ended 31 March 2021 were reviewed by the Audit Committee and have been approved and taken on record by the Board of Directors at its meeting held on 23 April 2021. The statutory auditors have issued unmodified audit report on these results.

2. The Board of Directors has declared 1st Interim Dividend of ₹ 6/- per equity share of ₹ 2/- each and a Special interim dividend of ₹ 10/- per equity share of ₹ 2/- each for FY 2021-22. The Special Interim Dividend has been declared by the Board in recognition of the Company's recent milestone, crossing the $10 Billion mark in Revenue during FY'21.

3. Financial results for all the periods presented have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (as amended from time to time) prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.

4. The Hon'ble National Company Law Tribunal of New Delhi and Bengaluru have approved the Scheme of Amalgamation providing for the merger of four direct /step-down wholly-owned subsidiaries engaged in providing IT and IT related services viz. HCL Eagle Limited, HCL Comnet Limited, HCL Technologies Solutions Limited and Concept2Silicon Systems Private Limited (the "Transferor companies") with and into HCL Technologies Limited (the "Transferee company") with effect from 01 April 2019, the appointed date. The scheme has become effective on 13 July 2020 on filing of the certified true copy of the Orders of the Delhi and the Bengaluru NCLT with the Registrar of Companies on 13 March 2020 and 13 July 2020 respectively.

Since the Transferor Companies are the wholly-owned subsidiaries of the Transferee Company, there will be no issue and allotment of shares as consideration. The difference between the amounts recorded as investments of the Company (Transferee Company) and the amount of share capital of the aforesaid amalgamating subsidiaries (Transferor Companies) has been adjusted in the Common Control Transaction Capital Reserve. The comparative results have been restated for all period presented as per guidance under Appendix C of Ind AS 103 "Business Combinations".

The impact of the scheme is not material on the standalone financial results of the company.

5. Employee benefit expenses for the three months and year ended 31 March 2021 for the Company and the Group includes ₹ 243 crores and ₹ 728 crores respectively, being the one-time special bonus paid to employees in recognition of achieving the $10 Billion revenue mark in year ended 31 March 2021.

6. Current tax expense for the three months ended 31 March 2021 includes ₹ 419 crores being the tax impact of goodwill taken out of purview of tax depreciation w.e.f. 1 April 2020 by Finance Bill enacted in March 2021. Also deferred tax expense for the three months and year ended 31 March 2021 includes ₹ 914 crores and ₹ 1,222 crores respectively being the Deferred Tax Liabilities recognized by the Company on difference between book basis and tax basis of goodwill consequent upon enactment of above provisions.

7. On 10 March 2021, the Company through its susbsidiary issued USD 500 million unsecured notes due 2026 (the "notes") for ₹ 3,656 crores. The notes bear interest at a rate of 1.375% per annum and will mature on 10 March 2026. Interest on the Notes will be paid semi-annually on 10 March and 10 September of each year, commencing from 10 September 2021. The Notes are listed on Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST). The notes were issued at the discount price of 99.510% against par value and has an effective interest rate of 1.58% p.a. after considering the issue expenses and discount of ₹ 35 crores.

8. The Indian Parliament has approved the Code on Social Security, 2020 which would impact the contributions by the group towards Provident Fund and Gratuity. The effective date from which the changes are applicable is yet to be notified and the final rules are yet to be framed. The Group will carry out an evaluation of the impact and record the same in the financial statements in the period in which the Code becomes effective and the related rules are published.

9. The figures of the last quarter are the balancing figures between audited figures in respect of the full financial year up to 31 March 2021 and the unaudited published year-to-date figures up to 31 December 2020 being the date of the end of the third quarter of the financial year which were subjected to a limited review.

10. The above is an extract of the detailed format of quarterly/annual financial results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formats of the quarterly/annual financial results are available on the websites of the Stock Exchanges, www.nseindia.com, www.bseindia.com, and on the Company's website, www.hcltech.com.

11. The disclosure in respect of standalone financial results as per SEBI circular SEBI/HO/DDHS/CIR/P/2018/144 dated 26 November 2018 with respect to identification of Large Corporate in the prescribed format of Annexure "A" and Annexure "B1" are as follows:

Annexure "A" Initial Disclosure to be made by entity identified as a Large corporate

Particulars	Details
Name of the Company	HCL Technologies Limited
CIN	L74140DL1991PLC046369
Outstanding borrowing as on 31 March 2021	₹ 225 Crores
Highest Credit Rating during the previous FY along with the name of the Credit Rating Agency	"AAA" ICRA Limited"
Name of the Stock Exchange in which the fine shall be paid, in case of shortfall in the required borrowing under the framework	National Stock Exchange of India Limited

We confirm that we are a Large Corporate as per the applicability criteria given under SEBI circular SEBI/HO/DDHS/CIR/P/2018/144 dated 26 November 2018.

Annexure "B1" Annual Disclosure to be made by entity identified as a Large corporate

1. Name of the company : HCL Technologies Limited
2. CIN : L74140DL1991PLC046369
3. Report filed for FY : FY 2020-21
4. Details of borrowings (all figures in ₹ crores) :

S. No.	Particulars	Details
i	Incremental borrowing * done in FY (a)	68
ii	Mandatory borrowing to be done through issuance of debt (b) = (25% of a)	17
iii	Actual borrowings done through debt securities in FY (c)	Nil
iv	Shortfall in the mandatory borrowing through debt securities, if any (d) = (b) - (c) { if the calculated value is zero or negative, write "nil"}	17
v	Reason for short fall, if any, in mandatory borrowings through debt securities	All new long term borrowings during the year have been made from the existing term loan arrangement that was sanctioned in FY'20 for funding needs for a specific project. The Company has not entered into any new borrowing arrangement during FY'21.

*Incremental borrowings mean any borrowing done during a particular financial year, of original maturity of more than 1 year, irrespective of whether such borrowing is for refinancing/repayment of existing debt or otherwise and shall exclude external commercial borrowings and intercorporate borrowings between a parent and subsidiary(ies).

By the order of the Board of Directors
for HCL Technologies Limited

Shiv Nadar – Chief Strategy Officer
C. Vijayakumar – President and Chief Executive Officer
Prateek Aggarwal – Chief Financial Officer

Noida (UP), India
23 April 2021

HCL